भारत सरकार

जलशक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

विषय: पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के संबंध में जून, 2021 माह का सारांश।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) में प्रगति

जून, 2021 महीने के दौरान 17,05799 परिवारों को कार्यशील घरेलू नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए। इस महीने के दौरान कार्यक्रम के तहत राज्यों को 1,313.87 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

स्वच्छ भारत मिशन -ग्रामीण चरण- II में प्रगति

जून, 2021 के दौरान, 94,180 व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (आईएचएचएल) और 3,407 सामुदायिक स्वच्छता परिसरों (सीएससी) का निर्माण किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत राज्यों को 319.52 करोड़ रुपये की धनराशि माह के दौरान जारी की गई है।

जेजेएम संबंधी वार्षिक कार्य योजना 2021-22

राजस्थान और महाराष्ट्र में ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग/ पीएचईडी के राज्य प्रभारी के साथ वर्ष 2021-22 के लिए क्रमशः जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन और वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रूप देने की समीक्षा करने के लिए वीडियो सम्मेलन बैठकों का आयोजन 25 जून, 2021 को किया गया।

असम में ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग/ पीएचईडी के राज्य प्रभारी के साथ राज्य में जल जीवन मिशन की प्रगति और कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री, असम और अपर सचिव एवं मिशन निदेशक (एनजेजेएम) की उपस्थिति में बैठक का आयोजन 26 जून, 2021 को किया गया।

सोशल ऑडिट संबंधी कार्यशाला

सोशल ऑडिट संबंधी आभासी कार्यशाला 15.06.2021 को डीडीडब्ल्यूएस, नई दिल्ली में अपर सचिव, एसबीएम (जी) की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। कार्यशाला में राज्य समन्वयक/परामर्शदाताओं ने भाग लिया। कुछ राज्यों ने सोशल ऑडिट में अपने अनुभव साझा किए।

सरपंच संवाद

"पंचायती राज संस्थाओं के साथ बातचीत" का आयोजन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीडीडब्ल्यूएस, नई दिल्ली से डीडीडब्ल्यूएस एसबीएम (जी) द्वारा 11 जून, 2021 को किया गया। मुख्य रूप से एसएलडब्ल्यूएम सहित स्वच्छता के क्षेत्र में उनके गांवों में सफलता की कहानियों, ओडीएफ स्थिरता, ओडीएफ प्लस के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों, 15 वें वित्त आयोग की निधि के प्रभावी उपयोग और कोविड महामारी से संबंधित पहल पर चर्चा हुई।

अन्य सरपंच संवाद - "पंचायती राज संस्थाओं के साथ बातचीत" का आयोजन वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीडीडब्ल्यूएस, नई दिल्ली से डीडीडब्ल्यूएस एसबीएम (जी) द्वारा 25 जून, 2021 को किया गया। संवाद में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों के सात जिला परिषद अध्यक्षों ने भाग लिया। मुख्य रूप से एसएलडब्ल्यूएम सहित स्वच्छता के क्षेत्र में सफलता की कहानियों, ओडीएफ स्थिरता, ओडीएफ प्लस के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों, 15वें वित्त आयोग की निधि के प्रभावी उपयोग पर चर्चा हुई।

*****